उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सूभाष रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 09 अगस्त, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–08(08/47)**

सचिव माध्यमिक शिक्षा डॉ.भूपिन्दर कौर औलख द्वारा जारी आदेश में जनपद उधमसिंहनगर के सितारगंज में पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु 67.10 लाख रूपये की अवशेष धनराशि स्वीकृत कर गई है।

इससे पूर्व इस पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु रूपये 92.25 लाख की लगात के सापेक्ष 25.15 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त दी गई थी।

देहरादून 09 अगस्त, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–07(08/46)**

सचिव माध्यमिक शिक्षा डॉ.भूपिन्दर कौर औलख द्वारा जारी आदेश में प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान राष्ट्रीय/राज्य/जनपद/ब्लॉक स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु 99,95,164 रूपये की धनराशि निदेशक माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध करा दी गई है।

इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग पर होने वाले व्यय के लिये 45,49,200 रूपये, 02 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं(फुटबाल अण्डर–19 बी एण्ड जी, हॉकी अण्डर 19 बी एण्ड जी) के आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय के भुगतान हेतु 1,93,604 रूपये, खेल शिविर पर होने वाले अनुमानित व्यय के लिये 2 लाख रूपये, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु जनपदों को दी जाने वाली अनुमानित धनराशि 12 लाख रूपये एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों के भोजन हेतु जनपदों को दी जाने वाली अनुमानित धनराशि 23,85,000 रूपये तथा अन्य व्यय की धनराशि सम्मिलित है।

देहरादून 09 अगस्त, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–06(08/45)**

सचिव माध्यमिक शिक्षा डॉ.भूपिन्दर कौर औलख द्वारा जारी आदेश में प्रदेश के 7 डाईट्स में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय कक्षों के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवशेष अन्तिम किश्त 169.85 लाख धनराशि स्वीकृत की गई है।

प्रदेश के 07 डाईट् में डायट अल्मोड़ा को 47.20 लाख रूपये, डायट चड़ीगांव पौड़ी को 09.96 लाख रूपये, डायट नई टिहरी को 07.97 लाख रूपये, डायट बड़कोट उत्तरकाशी को 43.11 लाख रूपये, डायट गौचर चमोली को 10.005 लाख रूपये, लोहाघाट चम्पावत को 41.60 लाख व डायट रतूड़ा रूद्रप्रयाग को 10.005 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

इससे पूर्व प्रदेश के 10 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में बहुउद्देशीय कक्षों के निर्माण हेतु औचित्यपूर्ण लागत रूपये 620.74 लाख रूपये के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रथम किश्त के रूप में रूपये 250.89 लाख रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में द्वितीय किश्त के रूप में 200 लाख रूपये इस प्रकार कुल 450.89(रूपये चार करोड़ पचास लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 09 अगस्त, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–05(08/44)**

शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक के नेतृत्व में लंदन गए प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को हीथ्रो हवाई अड्डे से संचालित पीआरटी (पर्सनल रैपिड ट्रांजिट) के कार्य प्रणाली की जानकारी ली। निर्धारित गाइड वेज पर चलने वाली पॉड इलेक्ट्रिक कार हैं। बताया गया कि स्वचालित पॉड पूरी तरह से कम्प्यूटराइज्ड हैं।

विशेषज्ञों ने जानकारी दी कि यातायात के दबाव को अल्ट्रा (अर्बन लाइट ट्रांजिट) से कम किया जा सकता है। गाइड वे बनाने के लिए ज्यादा जमीन की भी जरूरत नहीं है। पॉड कार के संचालन से हीथ्रो एयरपोर्ट पर प्रति वर्ष 200 टन कार्बन डाईऑक्साइड की बचत की जाती है। इसमें जीरो उत्सर्जन होता है। गाइड वेज और स्टेशन का निर्माण कम कीमत में बन जाता है। सवारी गाड़ी का इंतजार नहीं करना पड़ता है, बल्कि गाड़ी सवारी का इंतज़ार करती है। डिमांड पर हमेशा उपलब्ध रहती है। गंतव्य का चयन किया जा सकता है। उच्च स्तर की सुरक्षा रहती है।

इसके अलावा मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह 7–8 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों से मुलाकात की। खासतौर पर वैलनेस टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्योगपतियों से संपर्क कर निवेश सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

नई दिल्ली/देहरादून 09 अगस्त, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–04(08/43)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से उत्तराखण्ड के नेक रेटिंग के कॉलेजों को हिमालयी राज्यों की भाँति केन्द्रीय मदद उपलब्ध कराने तथा शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए जनपद हरिद्वार में मॉडल कॉलेज की स्थापना के साथ ही उत्तराखण्ड में प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री से यह भी अपेक्षा की कि नेक में नम्बर एक राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर को कलस्टर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाय। हिमालयी राज्यों के जो कॉलेज नेक में नहीं हैं, उन्हें भी रूसा के तहत अनुदान दिये जाने का अनुरोध मुख्यमंत्री ने मानव संसाधन विकास मंत्री से किया।

इस अवसर पर उपस्थित उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने केन्द्रीय मंत्री से सुमाड़ी के एनआईटी के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि पर एनआईटी के स्थायी कैम्पस के निर्माण का अनुरोध किया।

केन्द्रीय मंत्री श्री जावड़ेकर ने विभिन्न विषयों पर रखे गये प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

नई दिल्ली/देहरादून 09 अगस्त, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–03(08/42)**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 अक्टूबर को देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की।

- **मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से विभिन्न योजनाओं में सहायता के लिए अनुरोध किया।**
- **उत्तराखण्ड को प्रति वर्ष 5 हजार करोड़ का ग्रीन बोनस दिया जाए।**
- **विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं को जल्द स्वीकृतियां प्रदान की जाएं।**
- **वर्ष 2021 के हरिद्वार महाकुम्भ व आपदा संवेदनशील गांवों के विस्थापन के लिए विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की जाए।**
- **सौंग बांध परियोजना के वित्त पोषण व कोटद्वार में केंद्रीय आयुष अनुसंधान एवं शोध संस्थान की स्थापना का अनुरोध।**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 7 अक्टूबर को देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड डेस्टिनेशन इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन देहरादून में 7 व 8 अक्तूबर को होगा। गुरूवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उन्हें देहरादून में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान पर्यावरणीय सेवाओं के एवज में उत्तराखण्ड को प्रति वर्ष 5 हजार करोड़ रूपए का ग्रीन बोनस प्रदान करने, ग्रीन एकाउंटिंग प्रणाली बनाए जाने, विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं में आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने, चरेख डांडा, कोटद्वार में केंद्रीय आयुष अनुसंधान एवं शोध संस्थान की स्थापना करने, जनवरी से अप्रैल 2021 में होने जा रहे हरिद्वार महाकुम्भ के लिए विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करने, पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा प्रभावितों को राहत के लिए एसडीआरएफ के मानक राशि में वृद्धि करने व संवेदनशील गांवों के विस्थापन के लिए विशेष केंद्रीय सहायता दिए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों के स्बंध में पत्र सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया।

भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के सहयोग से किए गए एक अध्ययन के अनुसार उत्तराखण्ड प्रति वर्ष मात्र वन क्षेत्र से ही 95,112 करोड़ रूपए की पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। परंतु पर्यावरणीय कारणों से उत्तराखण्ड में विकास कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। राज्य की अनेक जलविद्युत परियोजनाएं रूकी पड़ी हैं। इससे कुल ऊर्जा आवश्यकता का 65 प्रतिशत अंश खरीदना पड़ रहा है। इसलिए राज्य द्वारा प्रदान की जा रही पर्यावरणीय सेवाओं को नेशनल एकाउंटिंग सिस्टम में शामिल किया जाए। इस प्रणाली के तहत ग्रीन डेफिसिट राज्यों से धनराशि एकत्र कर एक नेशनल एक्सचेंज का सृजन किया जाना चाहिए। इससे हरित आच्छादन के अनुसार संबंधित राज्यों को धनराशि का आवंटन किया जाए। जब तक यह प्रणाली नहीं बनती है तब तक उत्तराखण्ड को कम से कम 5 हजार करोड़ रूपए प्रति वर्ष ग्रीन बोनस के रूप में उपलब्ध करवाया जाए।

मुख्यमंत्री ने राज्य में जलविद्युत उत्पादन की सम्भावनाओं व विभिन्न परियोजनाओं के बारे में अवगत कराते हुए 300 मेगावाट की लखवाड़ परियोजना की स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से जल्द करवाने का आग्रह किया। उन्होंने 660 मेगावाट की किशाऊ परियोजना के ऊर्जा घटक का उचित वित्त पोषण व केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 300 मेगावाट की बावला नन्दप्रयाग जल विद्युत परियोजना की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति शीघ्र करवाए जाने के साथ ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से बावला नंदप्रयाग व 100 मेगावाट की नंदप्रयाग लंगासू परियोजना के लिए नए आवश्यक अतिरिक्त अध्ययन के लिए टर्म ऑफ रेफरेंसेज जारी करवाने का अनुरोध भी किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए उत्तराखण्ड को वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाएं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्वीकृत पैकेज के अनुरूप ही किए जाने का अनुरोध किया। उत्तराखण्ड में आयुष व आयुष से संबंधित शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन केंद्रीय आयुष अनुसंधान एवं शोध संस्थान की स्थापना की जा सकती है। इसके लिए चरेख डांडा, कोटद्वार में प्रदेश के आयुष विभाग के पास भूमि भी उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी से अप्रेल 2021 तक हरिद्वार में महाकुम्भ का आयोजन होना है। उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य के वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण महाकुम्भ की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में धनराशि आवंटित कराए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के उपरांत प्रभावितों को एस.डी.आर.एफ. से दी जाने वाली राहत के मानक पर्वतीय क्षेत्रों के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एस.डी.आर.एफ. से देय राहत राशि के मानकों में वृद्धि की जाए। प्रदेश के 350 से अधिक गांव आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। इन्हें अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से गौरीकुण्ड–केदारनाथ रोपवे को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र टिहरी में खोले जाने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम के लिए श्रद्धालुओं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 (हरबर्टपुर से बड़कोट) लम्बाई 111 किमी व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 (कोटद्वार से श्रीनगर) लम्बाई 137 किमी का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन मार्गों को भी चारधाम ऑलवेदर रोड परियोजना से जोड़ना आवश्यक है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से यातायात जाम की समस्या के निजात के लिए गंगा नदी पर कनखल से नीचे जगजीतपुर के निकट 2 किमी 500 मीटर लम्बाई के 4–लेन सेतु का निर्माण भी जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पेयजल की समस्या के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि पर्वतीय राज्य के संदर्भ में इसका उपाय यही उचित होगा कि विभिन्न बस्तियों के आस–पास से गुजरने वाले छोटी नदियों पर छोटे–छोटे जलाशय बनाए जाएं। इससे जलस्त्रोतों की रिचार्जिंग होगी और गुरूत्व आधारित योजना का निर्माण किया जाए। इसके लिए भारत सरकार के स्तर से लघु जलाशय/नद्य–ताल निर्माण की अलग से केंद्र पोषित योजना बनाई जाए। यदि ऐसा सम्भव न हो तो राज्य सरकार को बाह्य सहायतित परियोजना के लिए स्वीकृति दी जाए। नैनीताल जिले की गौला नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून की नगरीय व उपनगरीय आबादी को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शहर से 10 किमी दूर सौंग नदी पर 148.25 मीटर ऊंचा रोलर कॉम्पेक्टेड कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। इससे पेयजल की समस्या दूर होने के साथ ही रिस्पना व बिंदाल नदियों के पुनर्जीविकरण में भी सहायता मिलेगी। इसकी अनुमानित कुल लागत 978 करोड़ रूपए है। मुख्यमंत्री ने सौंग बांध परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार से करवाए जाने का आग्रह किया।

उत्तराखण्ड के सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में वर्तमान में केवल तीन हवाई पट्टियां निर्मित हैं। राज्य के सामरिक महत्व व आपदा की संवेदनशीलता को देखते हुए हवाई सेवाओं की सुविधाओं में विस्तार करना जरूरी है। एक सर्वेक्षण में अल्मोड़ा के चैखुटिया को हवाई पट्टी के निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया है। इसमें केंद्र सरकार से वित्तीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

गढ़वाल मण्डल से लगता सम्पूर्ण भू–भाग उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मण्डल के अधीन आता है जबकि कुमायूं मण्डल का सम्पूर्ण भाग पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मण्डल में आता है। इससे समन्वय की समस्या आती है। इसलिए राज्य के सम्पूर्ण भू–भाग को एक ही रेलवे जोन उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मण्डल के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लाईन पर कार्यवाही गतिमान है। इसके साथ ही सामरिक व पर्यटन महत्व को देखते हुए टनकपुर–बागेश्वर–कर्णप्रयाग रेलवे लाईन की स्वीकृति प्रदान की जाए। इसमें टनकपुर–बागेश्वर रेल लाईन का सर्वे किया जा चुका है।

हरिद्वार में स्थापित उद्योगों द्वारा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की मांग की जा रही है। हरिद्वार में बीएचईएल के पास उपलब्ध रिक्त भूमि में से लगभग 35 एकड़ भूमि राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित कर दी जाए तो लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा सकती है। इसके लिए भारत सरकार के भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्रालय को अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार जनपद नैनीताल के रानीबाग में स्थापित एचएमटी काफी वर्षों से बंद पड़ी है। यदि यह भूमि भी राज्य सरकार को निशुल्क मिल जाती है तो इसका उपयोग राज्य में औद्योगिक निवेश व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 09 अगस्त, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–02(08/41)

बुधवार को लंदन में शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक के नेतृत्व में विधायकों के प्रतिनिधिमण्डल ने रोपवे प्रणाली का निरीक्षण किया। दल ने विशेषज्ञों से इसकी क्षमता के बारे में जानकारी ली। यह भी समझने की कोशिश की गई कि क्या इस प्रणाली को उत्तराखण्ड में लागू किया जा सकता है। बताया गया कि यह पर्यावरण के अनुकूल प्रणाली है। अब तक लगभग एक करोड़ से ज्यादा यात्री इसका उपयोग कर चुके हैं।

लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त सभागार में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, सचिव स्वास्थ्य नितेश कुमार झा और सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा भारतीय मूल के ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन के साथ बैठक की। प्रस्तावित मेडिसिटी के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया गया। उत्तराखंड में विकसित किए गए पूंजी निवेश के अवसरों के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। राज्य में कार्यरत डॉक्टरों और पैरा मेडिक्स के कौशल उन्नयन में योगदान देने का अनुरोध किया गया। निवेशकों को अक्टूबर में उत्तराखंड में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

देहरादून 09 अगस्त, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(08/40)

सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन के लिए एम.ओ.यू शनिवार को

- **यू.एल.डी.बी. व इन्गुरान सेक्सिंग टेक्नोलॉजी, एलएलसी के मध्य एम.ओ.यू. का हस्तांतरण किया जाएगा।**
- **उतराखण्ड ही एकमात्र राज्य है जिसको श्यामपुर, ऋषिकेश में इस परियोजना की केंद्र से स्वीकृति मिली है।**
- **इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नर पशुओं की संख्या नियंत्रित कर मादा पशुओं की संख्या में वृद्धि करना है**
- **पशुधन भवन, मोथरोवाला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल, पशुपालन मंत्री श्रीमती रेखा आर्य व सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत भी उपस्थित रहेंगे।**

शनिवार 11 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन के लिए यू.एल.डी.बी. व इन्गुरान सेक्सिंग टेक्नोलॉजी, एलएलसी के मध्य एम.ओ.यू. का हस्तांतरण किया जाएगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल, पशुपालन मंत्री श्रीमती रेखा आर्य व सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत, विधायक धर्मपुर श्री विनोद चमोली भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन पशुपालन विभाग के मोथरोवाला रोड़ स्थित पशुधन भवन के प्रांगण में किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा नेशनल मिशन ऑन बोवाईन प्रोडक्टिवीटी के अंतर्गत परियोजना लाई गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नर पशुओं की संख्या नियंत्रित कर मादा पशुओं की संख्या में वृद्धि करना है ताकि दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके और देशी उच्च नस्ल के पशुओं का संरक्षण व संवर्धन किया जा सके।

उक्त परियोजना में भारत सरकार द्वारा देश के दस अग्रणी हिमीकृत वीर्य उत्पादन संस्थानों का चयन किया गया, जिसमें अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र, श्यामपुर ऋषिकेश भी शामिल था। इस परियोजना में प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने वाला उत्तराखण्ड प्रथम राज्य बना। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को उपयुक्त बताते हुए अपनी स्वीकृति दी। वर्तमान में उतराखण्ड ही एकमात्र राज्य है जिसको इस परियोजना की स्वीकृति मिली है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य देशी पशुओं के लिंग वर्गीकृत वीर्य का उत्पादन कर उसको गाय व भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग कर अधिक से अधिक मादा पशुओं को पैदा करना है, जिससे नर पशुओं की संख्या नियंत्रित किया जा सके व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके।

परियोजना की कुल लागत 47 करोड़ 50 लाख रूपए है जो पांच वर्षों के लिए संचालित की जानी है। इस परियोजना में 90 प्रतिशत केंद्रांश है जबकि 10 प्रतिशत राज्यांश है। इस परियोजना के पहले वर्ष में 2 लाख जबकि दूसरे, तीसरे, चौथे व पांचवे वर्ष में 3–3 लाख सैक्स सीमन डोज का उत्पादन किया जाएगा।

इस परियोजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड लाईवस्टाक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनी इन्गुरान एल.एल.सी. सेक्सिंग टेक्नोलॉजी से अनुबंध किया जा रहा है। यह कम्पनी विश्व की एकमात्र ऐसी कम्पनी है जिसको सेक्स सोर्टिंग ऑफ सीमन के काम में तकनीकी दक्षता हासिल है। इस विधि के द्वारा 'एक्स' व 'वाई' गुणसूत्र युक्त शुक्राणुओं को मशीन द्वारा अलग–अलग करके वीर्य स्ट्रा में पैक कर दिया जाता है। यदि मादा संतति की आवश्यकता है तो 'एक्स' क्रोमोसोम वाले वीर्य स्ट्रा का कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयोग करके मादा संतति की प्राप्ति की जा सकती है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग